

प्रेषक,

डी0एस0 गर्बाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 04-मार्च, 2014

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत नगर निकाय, नरेन्द्र नगर एवं लक्सर हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या: 1271/श0 वि0निदे0-729/2012, दिनांक 20.10.2012 एवं संख्या: 1748/श0वि0निदे0-729/2010, दिनांक 07.11.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत नगर पंचायत, लक्सर हेतु ₹105.18 लाख एवं नगरपालिका परिषद, नरेन्द्र नगर हेतु — ₹711.39 लाख के प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराये गये हैं।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, लक्सर के नाला निर्माण कार्य हेतु ₹105.18 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं नगरपालिका परिषद, नरेन्द्र नगर के संलग्न-1 में उल्लिखित कार्यों हेतु प्रथम चरण की लागत कुल ₹11.75 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्नक-1 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹61.93 लाख (इकसठ लाख तिरानवे हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि ₹61.93 लाख (इकसठ लाख तिरानवे हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सम्बन्धित नगर निकाय को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
4. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
6. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
7. उक्त धनराशि का दिनांक 31-3-2014 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
8. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

9. उपरोक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके साथ अद्यतन तिथि तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
10. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
11. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
12. प्रश्नगत कार्य की थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग हेतु प्रस्ताव नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 48.92 लाख, के अनुदान सं०-30 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-42 अन्य व्यय के नामे ₹ 11.15 लाख, तथा के अनुदान सं०-31 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 1.86 लाख डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा० सं०- 853/XXVII(2)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेंट आई डी-S1403130100, S1403300101 एवं S1403310102 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी०एस० गब्याल)
सचिव।

सं०- 211 (1)/IV(2)-शा०वि०-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास विभाग के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।

(सिने प्रमुख)
प्रमुख

शासनादेश संख्या: २११ /IV(2)-श0वि0-2014-45(सा0)12, दिनांक

मार्च, 2014 का संलग्नक।

क्र.सं.	कार्य का नाम	(धनराशि ₹ लाख में)	
		टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत	स्वीकृत धनराशि
1.	नगर पंचायत, लक्सर क्षेत्रान्तर्गत बसेड़ी रोड़ से धर्मशाला मुख्य बाजार/रेलवे फाटक तक मुख्य नाले का निर्माण कार्य	105.18	50.18
2.	नरेन्द्रनगर सुमन पार्क के समीप शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, टाउनहॉल, श्रीदेव सुमन पार्क एवं कार्यालय भवन का निर्माण	7.51 (प्रथम चरण की लागत)	7.51
3.	नरेन्द्रनगर बस स्टैण्ड के समीप कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स का निर्माण	4.24 (प्रथम चरण की लागत)	4.24
योग-			61.93

(₹ इकसठ लाख तिरानवे हजार मात्र)


 (ओमकार सिंह)
 उप सचिव।